



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1990/फाल्गुन 9, 1911

No. 77]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1990/PHALGUAN 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिगूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990

सा.का.नि. 99(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सिविल सेवा और समूह "ग" पद में रिक्तियों को भरने के लिए अधिशेष कर्मचारी पुनर्नियोजन नियमावली, 1967, केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद (समूह "घ") की रिक्तियों में अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति नियमावली, 1970, केन्द्रीय सिविल सेवा और पद (समूह "क" और "ख") अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन नियम, 1986 और केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन (अनुपूरक) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की रिक्तियों में अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द का पुनराभिनियोजन और पुनर्समायोजन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है।

(ख) "प्रकोष्ठ" से अभिप्रेत है,—

(i) समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" के अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का केन्द्राय (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द) प्रकोष्ठ;

(ii) समूह "घ" के अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के संबंध में श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महाविभाग का विशेष प्रकोष्ठ;

(ग) "आयोग" से संव लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो किसी केन्द्रीय सिविल सेवा या पद में भर्ती का विनियमन करने संबंधी नियमों

के अधीन, उस सेवा या पद में किसी रिक्ति को भरने के निर्णय करने और भरने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सक्षम है।

(ड.) “पुनर्मायोजन” से अभिप्रेत है इन नियमों के अनुसार किसी भूतपूर्व अधिशिष्ट कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति यद्यपि पहले से ही अन्य पद पर अभिनियोजित किया जा चुका है।

(च) “पुनराभिनियोजन” से इन नियमों के अनुसार किसी केन्द्रीय सिविल सेवा या पद में किसी रिक्ति में किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को नियुक्ति अभिप्रेत है।

(छ) “अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द” और “अधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों” से ऐसे केन्द्रीय सिविल सेवक (तदर्थ, आकस्मिक, निर्धारित कर्म या संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं जो—

(क) स्थायी हैं या यदि अस्थायी हैं तो उन्होंने पांच वर्ष से अन्यून नियमित निरन्तर सेवा की है, और [1]

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप उनके पदों के साथ अधिशिष्ट कर दिए हैं—

(1) प्रशासनिक और वित्तीय सुधार जिनके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ किसी संगठन को पुनर्संरचना करना, शून्य आधार बजट बनाना, किसी क्रियाकलाप का किसी राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य स्वायत्त संगठन को हस्तान्तरण करना, किसी चालू क्रियाकलाप को बंद करना और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को लागू करना शामिल है, या

(2) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकाद द्वारा या केन्द्रीय सरकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए कार्य मापन अध्ययन; या

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठन का पूर्णतः या भागनः उत्सादन या परिसमापन।

(ज) “पंजी” से अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द की ऐसी सूची अभिप्रेत है जो प्रकोष्ठ के माध्यम से सामयिक पुनर्नियोजन या पुनर्मायोजन के अधीन है।

3. प्रकोष्ठ को रिक्तियों की रिपोर्ट करना:

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद में समूह “क” और “ख” में रिक्तियाँ

(i) किसी समूह “क” या समूह “ख” सेवा या पद जिसमें कोई रिक्ति आयोग के माध्यम से (किंवा प्रतियोगी परीक्षा से अथवा आधार पर) सीधे भर्ती द्वारा भरी जाती है तो उस सेवा या पद से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी आयोग को इस प्रयोजन के लिए अध्यापिका भेजने के साथ-साथ उसकी एक प्रति प्रकोष्ठ को भी भेजेगा।

(ii) जब तक उसमें यह अनिवारित न हो कि उसकी एक प्रति समसामयिक रूप से प्रकोष्ठ को भेज दी गई है आयोग इस प्रयोजन के लिए भेजी गई अध्यापिका को ग्रहण नहीं करेगा और आयोग अधिसूचित किए गए पद की भर्ती के लिए सामान्य रीति से कार्य नहीं केवल तभी करेगा, जब—

(क) उसके कार्यालय में अध्यापिका को प्राप्त की तारीख से 15 दिन के भीतर, उक्त रिक्ति या रिक्तियों के स्थान पर प्रकोष्ठ द्वारा अधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रयोजन करने की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती, या

(ख) प्रकोष्ठ द्वारा विचार के लिए सिफारिश किया गया/किए गए अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रस्ताधीन पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है/पाए जाते हैं।

(iii) जहां कोई पद आयोग के परामर्श से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है, तो उस पद से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी रिक्ति पहले प्रकोष्ठ को सूचित करेगा जो यदि उस पर नियुक्ति के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उसकी पंजी में है तो संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देते हुए, प्रस्ताधीन पद पर आमेलन के लिए विचार किए जाने के लिए उसे आयोग को प्रयोजित करेगा। उक्त पद केवल तभी परिचालित किया जाएगा यदि (क) प्रकोष्ठ उस पर आमेलन के लिए अपनी पंज में से प्रयोजित करने के लिए उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारी अनुपलब्ध होना सूचित करता है या (ख) आयोग पद पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोजित अधिशिष्ट कर्मचारी को अनुपयुक्त पाता है।

(iv) समूह “क” और समूह “ख” में केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में सभी रिक्तियाँ जो आयोग के माध्यम से अन्यथा, सीधे भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा भरी जाती हैं, पहले प्रकोष्ठ को रिपोर्ट की जाएंगी और अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से भरी जायेंगी, जब तक कि प्रस्ताधीन पद या सेवा के नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रकोष्ठ से यह अनिवारित न कर लिया हो कि विशिष्ट पद पर नामित करने के लिए उसके पास अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।

(v) उप नियम (1) में अंशित उपबंध निम्नलिखित के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन पद और सेवाओं को लागू नहीं होंगे:

(क) (i) परमाणु ऊर्जा (ii) अंतरिक्ष (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स (iv) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा (v) रेल (रेल-बोर्ड के मुखाधाय कार्यालयों में अवस्थित पदों को छोड़कर) विभाग;

(ख) रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से निम्न निम्न क्षेत्र विरचनाएं),

(ग) गृह और रक्षा मंत्रालयों तथा संविधान सचिवालय के अधीन विभिन्न सुरक्षा और परामर्श संगठन

परन्तु यह इन सेवाओं और पदों के नियंत्रक प्राधिकारी को प्रकोष्ठ से उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारियों को प्रयोजित करने का अनुरोध करने तथा उन्हें नियुक्त करने में बाधा नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद समूह “ग” और समूह “घ” में रिक्तियाँ

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद समूह “ग” और “घ” में सभी रिक्तियाँ सिवाए उनके जो इस उपनियम के खंड (3) और उपनियम (4) के खंड (क) के अन्तर्गत प्रस्ता हैं संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएंगी।

(2) सरकारी विभाग या कार्यालय संबंधित प्रकोष्ठ से यह अनिवारित कर लेने के परन्तु हो कि किसे विशिष्ट पद के लिए उसके पास उपलब्ध अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में उपयुक्त व्यक्ति नहीं है सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियाँ भर सकेंगे।

(3) निम्नलिखित प्रवर्गों की रिक्तियाँ संबंधित प्रकोष्ठ को रिपोर्ट नहीं की जाएंगी:

(क) जो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जाती हैं;

(ख) जो तदर्थ या अल्पकाल आधार पर भरी जाती हैं, जिन पर नियुक्ति अनिवारित काल तक चालू रहने और अंत में नियमित किए जाने की सम्भावना नहीं है।

(ग) जो प्रोन्नति कांडर (रॉ) में प्रोन्नति के लिए बहिष्कृत रखने वाले पाद अभ्यर्थी उपलब्ध हैं;

(घ) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (क) और (ख) उल्लिखित मंत्रालयों या विभागों में अवस्थित हैं;

(ड) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (ग) में उल्लिखित संगठनों में अवस्थित हैं और जो खाली भर्ती में अथवा माध्यम से भरी जाती हैं

(च) जो किसी उच्चतर पदस्थ के निजी स्टाफ के पद में हैं और उन पर नियुक्ति उस उच्च पदस्थ के विवेकाधिकार से की जानी है,

(च) जो मृतक सरकारी सेवक पर अश्रित(तां) की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरी जाती हैं;

(ज) जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय अश्रुलिपिक सेवा, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में हैं;

(झ) जो नियम 4 के उपनियम (6) और नियम 12 के अर्थात् नियुक्तियाँ किए जाने में उपयोग की जा रही हैं।

(3) रिक्तियों का प्रत्याहरण

कोई रिक्ति जो प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई है और जिसके लिए कोई अधिशिष्ट कर्मचारी या तो प्रकोष्ठ द्वारा नामित किया गया है या अगर उपनियम (1) के खंड (1) या (3) के अर्थात् रिपोर्ट की गई रिक्ति के मामले में, आयोग द्वारा सिफारिश किया गया है, प्रत्याहरित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी रिक्ति का प्रत्याहरण आवश्यक समझा जाए वहाँ प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव द्वारा या उसके स्पष्ट अनुमोदन से, उसके लिए कारण देते हुए अनुरोध किया जाएगा।

परन्तु यह और कि रिक्ति के प्रत्याहरण की आवश्यकता और औचित्य के संबंध में किसी शंका या विवाद के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्णय का पालन करेगा।

(4) प्रकोष्ठ की रिक्तियों की चरित्रात्मक रिपोर्टें किया जाना :—

“उप नियम (1), (2), और (3) में अर्थात् किन्हीं बात के होते हुए भी संबंधित प्रकोष्ठ अनुदेश जारी कर सकेगा कि,—

(क) मंत्रालयों और विभागों की कतिपय ऐसे पदों, श्रेणियों, सेवाओं या क्षेत्रों में जो विनिर्दिष्ट किए जाएँ रिक्तियाँ या तो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि प्रतिकूल अनुदेश जारी नहीं कर दिए जाते रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) किन्हीं विशिष्ट पदों, श्रेणियों, सेवाओं या क्षेत्रों में किसी समय विद्यमान रिक्तियों की रिपोर्ट उसे की जाए और उन्हें किसी अन्य तरीकों के माध्यम से जिनमें ऐसे तरीके भी सम्मिलित हैं जो भर्ती नियमों में विहित किए गए हैं न भरा जाए और ऐसा पूर्वोक्त प्रकोष्ठ से विनिर्दिष्ट अनापत्ति प्राप्त करके ही किया जाए, अन्यथा नहीं।

4. अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन

(i) मनुह “क” और मनुह “ख” सेवाओं या पदों में रिक्तियों पर (1) समूह “क” तथा “ख” सेवाओं और पदों में रिक्तियों, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा, जिनमें आयोग द्वारा भरी जाने वाली (आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, परीक्षा से अथवा आधार पर) या स्थानांतरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ शामिल हैं, पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए अधिशेष कर्मचारी प्रथम अग्रता के हकदार होंगे।

परन्तु यह तब जब कि वे आयोग या अन्य विहित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और ऐसा रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उनके पास कोई उपयुक्त असमर्थ रक्षा सेवा कामिक उपलब्ध नहीं है।

(ii) प्रकोष्ठ ऐसे अधिशिष्ट कर्मचारियों के नाम की जो तत्समय उसकी पंजी पर है, किसी विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए, जिसमें रिक्ति आयोग और प्रकोष्ठ को अधिसूचित की गई है और जिस पर नियुक्ति के लिए संबंध अधिशिष्ट कर्मचारी उस पद के और उसके द्वारा धारित पद के वेतनमान, उसकी अर्हताओं और उसके पूर्व अनुभव को

सुसंगतता को देखते हुए प्रकोष्ठ को प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत होता है, आयोग को सिफारिश करेगा;

(iii) प्रकोष्ठ अपनी पंजी में से एक से अधिक कर्मचारियों की किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का सिफारिश कर सकेगा जिसके लिए उनमें से प्रत्येक उसकी नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है;

(iv) आयोग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर, जिसका जीवनवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर नियुक्ति के लिए विचार कर सकेगा, भले ही प्रकोष्ठ द्वारा, उसकी उस पद के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश न की गई हो; परन्तु यह तब जब कि (क) प्रस्तुत पद का वही वेतनमान या वेतनमान का अधिकतम वही है जो उसके द्वारा धारित पद का है (ख) अधिशेष कर्मचारी अन्य पदों के जिनके लिए उसकी अभ्यर्थिता प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित की गई हो, अधिमान में ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है और (ग) वह इस उपनियम के खंड (5) में वर्णित असमर्थताओं से ग्रस्त नहीं है।

(V) प्रकोष्ठ किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के नाम की आयोग को सिफारिश नहीं करेगा—

(क) यदि प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित किए जाने पर आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में उसके विद्यमान वेतनमान से अनिम्नतर वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के लिए उसकी पहले ही सिफारिश की जा चुकी है;

(ख) यदि उसने इसी दौरान किसी अन्य पद का कार्यभार चाहु प्रकोष्ठ के माध्यम से पुनराभिनियोजन पर या अन्यथा संभाल लिया है या उसके किसी अन्य सतत पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, प्रतिवर्तन के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि प्रकोष्ठ की पंजी पर उसके अन्तर्ण की तारीख से छः मास के भीतर अधिवर्षिता प्राप्त कर लेगा ;

(घ) यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं या उसे सेवानिवृत्त (जिसके अन्तर्गत अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा दी गई समयपूर्व या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की मूचना पर सेवा निवृत्ति है) किया जाता है या सेवान्मुक्त कर दिया गया है या वह प्रकोष्ठ की पंजी में उसके अन्तर्ण की तारीख से छह मास की ममाप्ति के पूर्व किसी दिन को प्रकोष्ठ की पंजी पर अन्यथा नहीं रह जाता है,

(ङ) नियम 5 में अधिकथित स्थानन का परिधि के बाहर आने वाले किसी पद में आमेजन के लिए।

(vi) आयोग, किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर पहले लिखी गई गोपनीय रिपोर्टें स्वाविवेकानुसार देख सकेगा या यदि आवश्यक हो, तो किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए उसे सहायक के लिए बुला सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए उसकी लिखित परीक्षा नहीं लेगा।

(vii) आयोग, अपने विवेकानुसार प्रकोष्ठ द्वारा उस सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए प्रयोजित अधिशिष्ट कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य के संबंध में किसी सेवा या पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि में छूट दे सकेगा यदि वह अधिशिष्ट अभ्यर्थी को विचारार्थता सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त समझता है।

(viii) आयोग, किसी पद के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए किसी अधिशिष्ट कर्मचारी का अंतिम रूप से उपयुक्तता

या अन्यथा का निर्धारण और प्रकोष्ठ को उसकी सूचना अपने कार्यालय में ऐसी सिफारिश की प्राप्त की तारीख से अथवा एक मास के भीतर करेगा।

(2) समूह "ग" और समूह "घ" सेवाओं में या पदों में रिक्तियाँ

(i) प्रकोष्ठ द्वारा नामांकित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द किसी रिक्त पर नियुक्ति के लिए असमय सेवा कामिक के पश्चात् प्रथम अग्रतः के हकदार होंगे।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद समूह "ग" या समूह "घ" की रिक्तियों में पुनराभिनियोजन के लिए यथास्थिति संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी परीक्षा या साक्षात्कार के अध्वोचन नहीं होंगे जब तक कि संबंधित प्रकोष्ठ अथवा इसके परामर्श से अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

(iii) उन मामलों को छोड़कर जहाँ किसी विशेष पद के लिए कतिपय तर्कों की अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द प्राप्तिकर्ता संगठनों में नियुक्ति के लिए इस आधार पर अपात्र नहीं होंगे कि उनके पास उन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं हैं जिस पर उन्हें प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित किया गया था ;

परन्तु जहाँ कोई अधिशिष्ट कर्मचारी नियमित आधार पर कोई समतुल्य पद सम्भूत रूप से समान कर्तव्यों के साथ पहले ही भारण कर रहा है वह पद पर नियुक्ति के लिए केवल इस आधार पर कि उसके पास पद पर नियुक्ति के विहित शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं नहीं हैं अनुपयुक्त नहीं माना जाएगा, यदि उसने उस पर परीक्षा संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर ली है या यदि उस परीक्षाओं नहीं रखा गया था और विगत 2 वर्ष से अन्यून अवधि में उसका काम संतोषप्रद रिपोर्ट किया गया था।

(iv) यदि कामिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रकोष्ठ, उसको रिपोर्ट की गई रिक्तियों के पुनरावलोकन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समूह "ग" पद में उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था करना उसे संभव नहीं होगा तो वह यथाशक्य, रोजगार और प्रशिक्षण महाविदेशालय में प्रकोष्ठ को पूर्व सूचना देकर समूह "घ" सेवा या पद में किसी रिक्ति पर किसी समूह "ग" अधिशिष्ट कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकेगा और उसे उस स्थिति में ऐसे नामांकन पर यह नियम उजा प्रकर लागू होंगे जैसे उक्त महाविदेशालय में प्रकोष्ठ द्वारा किए गए समूह "घ" अधिशिष्ट कर्मचारी के नामांकन पर लागू होते हैं ;

परन्तु यह कि जहाँ एक ही रिक्ति के लिए नामांकन कामिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही साथ रोजगार और प्रशिक्षण महाविदेशालय द्वारा किया गया है प्राप्तिकर्ता संगठन को पहले प्राप्त नामांकन पर कार्यवाही करेगा और दूसरे संगठन को अपना नामांकन अग्रतः प्रत्यावर्तित करने के लिए संयुक्त करेगा।

(3) अधिशिष्ट स्थापित कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन

(क) कोई कर्मचारी, जो किसी पद पर स्थापित है अधिशेष घोषित कर दिया जाता है नियम 5 का उपनियम (1) का खण्ड

(i) के अनुसार किसी पद पर पुनराभिनियोजन का पात्र होगा, परन्तु यह कि --

(i) वह उस पद पर प्रोन्नति का नियमित प्रक्रिया या स्थापनाकरण के माध्यम से नियुक्ति किया गया था और उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिशेष घोषित किया गया है छह माह

को अवधि के भीतर, सामान्य अनुक्रम में उसके उससे प्रतिवर्तन की कोई संभाव्यता नहीं थी

(ii) वह स्वयं उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार है प्रतिवर्तित होने के लिए विकल्प नहीं लेता है और

(iii) पूर्वक छ माह का अवधि के भीतर किसी तारीख से से वह उसे लागू नियमों के अधीन अधिवर्षित होने वाला नहीं है और न ही उसे सेवा निवृत्ति की अनुज्ञा दिये जाने के लिए कहा है।

(ख) अधिशिष्ट स्थापित कर्मचारी उस तारीख से जिस से अधिशेष घोषित किया गया था छह माह की समाप्ति पर उस पद पर प्रतिवर्तित हो जावेगा जिस पर उसका चाहे प्रशासनिक या अधिष्ठाया धारणाधिकार, है (जब तक कि वह पद समाप्त या अधिशेष घोषित न किया जा चुका हो) यदि उक्त अवधि के भीतर उसके लिए किसी समुचित पद पर नियोजन की व्यवस्था न की जा सके या उसके नियोजन के लिए की गई व्यवस्था को वह अस्वीकार करता है या उस अधिकारी जिसके अधीन वह नियोजन अवति है द्वारा समुचित कार्य ग्रहण को अवधि के भीतर उक्त नियोजन पर पद ग्रहण करने में विफल रहता है।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के प्रावधान किसी उन कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे जिसने उसके द्वारा धारित पद पर परीक्षा संतोषप्रद रूप से पूरी कर ली है या सक्षम प्राधिकारों के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन उक्त स्थापनापन्न नियुक्ति पर उसे परीक्षा पर रखे जाने से छूट प्राप्त थी।

(4) आयोग के माध्यम से भिन्न भरे पदों पर नियुक्ति के लिए अधिशेष कर्मचारियों को उपयुक्तता का अवधारण :

निम्नलिखित प्राधिकारियों को, आयोग के माध्यम से अन्यथा भरे पदों पर नियुक्ति के लिए नांचे दशित अनुसार जहाँ आवश्यक हो सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन विहित अर्हताओं, अनुभव आदि को शिथिल करके, अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द की उपयुक्तता का अवधारण करने का अधिकार होगा :

(क) कामिक और प्रशिक्षण विभाग उन कर्मचारियों की बाबत जो निम्नलिखित के लिए नामांकित किए गए हैं :--

(1) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (iv) के अधीन रिपोर्ट की गई समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं और पदों में रिक्तियाँ ;

(ii) उनको छोड़कर जो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (v) में वर्णित मंत्रालयों, विभागों आदि में अवस्थित हैं समूह "ग" सेवाओं और पदों में रिक्तियाँ और

(iii) समूह "ग" अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के पुनराभिनियोजन के लिए इस नियम के उपनियम (2) के खंड (iv) के अधीन उपयोग की गई समूह "घ" सेवाओं और पदों में रिक्तियाँ ;

(ख) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (5) में वर्णित मंत्रालयों, विभागों आदि में रिक्तियों के विरुद्ध नामांकित व्यक्तियों की बाबत संबंधित मंत्रालय या विभाग।

(ग) उक्त भिन्न जो ऊपर उपनियम (2) के खंड (iv) में निर्दिष्ट हैं, समूह "घ" सेवाओं और पदों के प्रति नामांकित समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में महाविदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण, भ्रम मंत्रालय।

(5) आयोग या प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए अधिशिष्ट कर्मचारियों को नियुक्ति :

(i) प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को किसी ऐसे पद या सेवा पर नियुक्ति के लिए जिसके लिए यथास्थिति आयोग या प्रकोष्ठ से पहले अध्यापका की गई थी

आयोग द्वारा की गई सिफारिश या प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए नामांकन की प्राप्ति पर मंयद अधिशिष्ट कर्मचारी को नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा और उसकी सूचना प्रकोष्ठ को और जहां सुसंगत हो, आयोग को देगा।

(ii) प्राप्तिकर्ता संगठन का नियुक्ति प्राधिकारी तत्काल अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन का विनियमन करने वाले निबंधनों और शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा और निवाए जहां कि किसी विधि द्वारा अपेक्षित हो, प्रकोष्ठ के बिना पूर्व परामर्श किए स्वयं की कोई विपरीत शर्त अधिरोपित नहीं करेगा।

(iii) प्राप्तिकर्ता संगठन किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को प्रतिग्रह करेगा जिसे एक माह के भीतर इसके किसी प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया के अभाव में संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर मूल संगठन से भार मुक्त कर दिया गया है।

(6) मंत्रालय या विभाग के भीतर ही अधिशिष्ट कर्मचारियों का आगमन

उप नियम (2), (3), (4) और (5) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी और नियम 12 के प्रावधानों के अधीन मंत्रालय या विभाग-अध्यक्ष, किसी कर्मचारी को जो इस द्वारा अधिशिष्ट घोषित किया गया हो, को संबंधित प्रकोष्ठ को सूचित करते हुए, किसी ऐसे पद में रिक्ति पर यदि कोई उसके अधिशिष्ट घोषित करते समय या प्रकोष्ठ द्वारा उसके (पुनराभिनियोजन से पहले उपलब्ध हों) समायोजन कर सकेगा, जो कि उसके नियंत्रण अधीन किसी कार्यालय में अवस्थित हो, और जिसका समान वेतनमान हो, जिस पर नियुक्ति के लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है,

अधिशिष्ट कर्मचारी के पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही की समाप्ति

किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएगी, जिसको—

(क) उसे उसी या किसी दूसरे विभाग या संगठन में अन्य पद ग्रहण करने के लिए, चाहे उसकी व्यवस्था प्रकोष्ठ के माध्यम से की गई हो या अन्यथा, सेवान्मुक्त किया गया है; या

(ख) सेवा के पर्यवसान अथवा त्यागपत्र अथवा स्वैच्छिक या समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है।

5 स्थान का अवधारण

(1) (i) कोई अधिशिष्ट कर्मचारी, उसकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यथाशक्य ऐसे पद में पुनराभिनियोजित किया जायगा जिसका वेतनमान उसके वर्तमान वेतनमान से तुलनीय है।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए तुलनीय वेतनमान से वह वेतनमान अभिप्रेत होगा जिसका अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम के बराबर है और जिसका न्यूनतम उस मूल वेतन से (वृद्धिरुद्ध वेतन समेत) से अधिक नहीं है जो अधिशिष्ट कर्मचारी नामांकित किए जाते समय प्राप्त कर रहा है।

(2) जहां तुलनीय वेतनमान वाले किसी उपयुक्त पद में रिक्ति उपलब्ध नहीं है वहां अधिशिष्ट कर्मचारी किसी गैर तुलनीय वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित किया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि—

(i) ऐसे पद के वेतनमान का अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है; और

(ii) ऐसा पद उस पद से निम्नतर नहीं है जो अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा तत्समय धारित पद के स्तर वाले पदधारियों के लिए प्रोत्साहक सौपान में आगामी निम्नतर पद है या सामान्यतः आगामी निम्नतर पद होगा :

परन्तु यह और भी कि—

(i) उपरोक्त पहले परन्तु के खंड (i) के निबंधनों के अनुसार किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को जो किसी उच्चतर अधिकतम वेतनमान वाले किसी पद के लिए प्रयोजित या नामांकित किया गया है या उसके पास या तो पद पर सीधी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए यथाविहित अर्हताएं होनी चाहिए, या अपने मूल विभाग में ऐसे पद से संलग्न कर्तव्यों का निर्वहन वह सफनतापूर्वक कर रहा हो, और

(ii) जब किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को निम्न वेतनमान वाले किस पद पर पुनराभिनियोजित किया जाता है उसे अगले पद पर अपने चालू वेतनमान के साथ ले जाने की अनुज्ञा दी जाए परन्तु यह फायदा तब नहीं दिया जायगा जब किसी तुलनीय या उच्चतर वेतनमान में किसी पद की उपलब्धता के बावजूद किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के अनुरोध पर किसी निम्न-वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजन किया गया है।

(3) जहां कोई अधिशिष्ट कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 में विहित वेतनमानों से भिन्न किसी वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा है, प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कर्मचारी के पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ को उसके विवरणों की रिपोर्ट करते समय या उसके पश्चात् यथाशीघ्र उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं और उसमें संलग्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उसके वेतनमान के पूर्वोक्त नियमों के अधीन तत्सम वेतनमान जैसा कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से अवधारित किया जाए, भी प्रकोष्ठ को संसूचित करेगा। इस नियम के अधीन और नियम 6 के अधीन उसके स्थान के प्रयोजन के लिए कर्मचारी उक्त पुनरीक्षित वेतन नियम के उस तत्सम वेतनमान जो कि इस नियम के अधीन अवधारित किया गया है, का धारक माना जायगा।

6 धारपुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनर्समायोजन :

(1) कोई अधिशिष्ट कर्मचारी, जिसे पहले ही पुनराभिनियोजित किया जा चुका है, निम्नलिखित हालातों को छोड़कर पुनसमायोजन की मांग करने के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) जब वह अपने अनुरोध से अन्यथा—

(i) किसी ऐसे पद पर, जिसका वेतनमान उस वेतनमान से निम्नतर है, जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय था; या

(ii) किसी पद पर, जो वर्गीकरण में उस पद से निम्नतर है, जिसे वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण किए था; या

(iii) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसका अधिकतम वेतनमान केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अनुसार 2900 रुपये से अधिक नहीं है उस/उन राज्य (यों) से भिन्न किसी राज्य में जिसमें/जिनमें उसने पुनराभिनियोजन की प्रतीक्षा करते समय अपने ग्यान को व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया था और ऐसे अनुरोध के अभाव में, जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था।

पुनराभिनियोजित किया गया है ;

परन्तु यह कि वह, यथास्थिति, चुनाव या तैनाती के ऐसे राज्य(यों) में अंतर विभागीय स्थानांतरण पाने के लिए सामान्य अनुक्रम में पात्र नहीं है :

परन्तु यह और कि वह उन प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसमें अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है ।

(ख) यदि उसका मामला, किसी अन्य ऐसे मामलों के वर्ग के अन्तर्गत आता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) कोई पुनराभिनियोजित कर्मचारी, जो उपनियम (1) के निबन्धनों के अनुसार पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र है परिशिष्ट में दिए गए प्राव्य में ऐसे पुनः समायोजन के पक्ष में विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे उस पद के, जिसमें वह तत्समय पुनराभिनियोजित किया गया है, ग्रहण की तारीख से दो मास के भीतर अपने कार्यालय के प्रधान के माध्यम से कामिक और प्रशिक्षण विभाग (अधिशेष प्रकोष्ठ) को या समूह "घ" कर्मचारी की दिशा में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली को भेजेगा ।

(3) यदि विकल्प स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो कर्मचारी का विद्यमान पुनराभिनियोजन अन्तर्लिप्त माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी "अधिशेष कर्मचारीवृन्द" पद की परिभाषा में अन्तर्लिप्त किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, काल्पनिक रूप से अंतिम पुनराभिनियोजन के लिए प्रस्तावित अधिशेष कर्मचारी माना जाएगा ।

(4) पुनः समायोजन निम्नलिखित और शर्तों के अधीन होगा—

(क) अधिशेष कर्मचारी का अपनी पूर्व सेवा की, जिसके अन्तर्गत वह भी है, जो उसके अन्तर्लिप्त पुनराभिनियोजन के पद में की गई है, उस पद में, जिसमें वह पुनः समायोजित किया गया है, ज्येष्ठता के नियतन के लिए गणना के लिए कोई दावा नहीं होगा ;

(ख) पुनः समायोजन के लिए कारंवाई समाप्त हुई मानी जाएगी—

(i) उस तारीख से, जिसकी पुनः समायोजन के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, छह मास की समाप्ति पर (जिसके अन्तर्गत निर्लंबन/अनुशासनिक कार्यवाहियों की यदि कोई हो, अवधि नहीं है); या

(ii) ऐसे पूर्वोक्त तारीख की, जिसकी ऐसे पद में, जिसका समरूप बेतनमान है और या उनके बारे में, जो उपर्युक्त उपनियम (1) खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) के अन्तर्गत आते हैं समतुल्य वर्गीकरण है; और उनके बारे में, जो उसके खंड (iii) के अन्तर्गत आते हैं, समुचित राज्य में, कर्मचारी को नियुक्ति का कोई प्रस्ताव किया जाता है, या

(iii) यदि वह पुनः समायोजन के लिए विकल्प वापस लेता है या त्यागपत्र देता है या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्यथा सेवा में नहीं रहता है; और

(iv) उस कर्मचारी की दशा में, जो निर्लंबनाधीन है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के अध्वधीन हो जाता है, यथास्थिति, ऐसे निर्लंबन या अनुशासनिक कार्यवाहियों के चालू रहने की अवधि के दौरान ।

(ग) पुनः समायोजन केन्द्रीय मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में उपलब्ध और संबंधित प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए ही किया जाएगा ।

(घ) उच्चतर बेतनमान वाले पद पर पहले से ही पुनराभिनियोजित किसी अधिशेष कर्मचारी को, किसी ऐसे पद पर समायोजित किया जा सकेगा जिसका बेतनमान उसके मूल बेतनमान के तुलनीय है और वह ऐसे उच्चतर बेतनमान वाले पद पर समायोजित किए जाने के लिए कोई दावा नहीं रखेगा और न ही वह नए पद पर ऐसे उच्चतर बेतनमान के संरक्षण के लिए हकदार होगा ।

(ङ) निम्नतर बेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित ऐसा अधिशेष कर्मचारी जो उपरोक्त उपनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन पुनः समायोजन चाहता है, कामिक विभाग और प्रशासनिक सुधार के का.जा.सं. 1-15-84-सी.एत.-II तारीख 3-9-84 के निबन्धनों के अनुसार प्रास्थिति के संरक्षण का पात्र होगा, यदि अंतिम रूप से भी उसे निम्नतर वर्गीकरण वाले पद पर पुनः समायोजित कर लिया जाता है किन्तु वह उस कारण से आगे पुनः समायोजन मांगने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(च) आरंभिक पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षा करने वाले अधिशेष कर्मचारियों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा, यथास्थिति, कामिक और प्रशिक्षण विभाग या नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय को रिपोर्ट की गई रिक्तियों के संबंध में समायोजन के लिए पहला दावा होगा और अन्तिम रूप से पुनराभिनियोजित कर्मचारियों के समायोजन की संभावना की खोज रिपोर्ट की गई शेष रिक्तियों के संबंध में की जाएगी जिन्हें भर्ती की सामान्य प्रणालियों के माध्यम से भरी जाने के लिए पहले से अनुज्ञात नहीं किया गया है ।

(छ) किसी विशिष्ट जिला या शहर या विभाग या पद में समायोजित किए जाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5) इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार पुनः समायोजन के रूप में किसी कर्मचारी की नियुक्ति को स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण अवधि और कार्यग्रहण अवधि के बेतन मंजूर करने के लिए लोकहित में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति माना जायगा ।

(6) इन नियमों के अधीन पुनः समायोजित किए जाने पर किसी कर्मचारी की स्थायी प्रास्थिति और पिछली सेवाओं के संरक्षणों के फायदे उन्ही शर्तों पर अनुज्ञेय होंगे जो पुनराभिनियोजित किए जाने पर किसी अधिशेष कर्मचारी के संबंध में लागू होंगे ।

(7) नियम 3 के अधीन प्रस्तुत प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई रिक्तियों का उपयोग इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार पुनराभिनियोजित कर्मचारियों के पुनः समायोजन के लिए समुचित प्रकोष्ठ द्वारा किया जा सकेगा यदि सुसंगत समय पर उन रिक्तियों के संबंध में नामनिर्दिष्ट किए जाने/प्राप्त किए जाने के लिए कोई उपयुक्त अधिशेष कर्मचारी नहीं है ।

(8) इन नियमों के नियम 4 (उसके उपनियम (1) के खंड (v) का उपखंड (क) और (ख) तथा उपनियम (7) को छोड़कर (5, 7, 8, 9 और 10 में अन्तर्लिप्त उपबंध पुनराभिनियोजित अधिशेष कर्मचारियों के पुनः समायोजन के संबंध में भी लागू होंगे ।

(9) पुनः समायोजन के लिए किसी कर्मचारी के विकल्प का स्वीकार किया जाता उसे ऐसा कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने, कोई विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने से, जो उसके द्वारा धारित पद को लागू नियमों द्वारा है, या सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के अधीन अन्तिम पुनराभिनियोजन के कार्यालय में उससे अपेक्षित हो, स्वभावतः उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा ।

7. आयु सीमा : इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी अधिशेष कर्मचारी की दशा में उच्चतर आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

8. चिकित्सीय परीक्षा—प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित अधिशेष कर्मचारिवृन्द से नए सिरे से चिकित्सीय परीक्षा करवाने की अपेक्षा नहीं

की जाएगी जब तक कि प्राप्तिकर्ता संगठन में पद के लिए भिन्न चिकित्सीय मान विहित न किए गए हों या जब तक कि संबंध व्यक्ति की उसके पूर्ववर्ती पद के लिए चिकित्सीय परीक्षा न हुई हो या यदि हो गई हो तो उसे चिकित्सक दृष्टया अयोग्य घोषित किया गया था।

9 वेतन और ज्येष्ठता का नियत किया जाना, विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए पूर्व सेवा की गणना और धारणाधिकार/वर्गीकरण का अग्रनयन—अधिशिष्ट कर्मचारी की नए पद में, जिस पर वह इन नियमों के अधीन पुनराभिनियोजन पर नियुक्त किया जाता है, ज्येष्ठता और वेतन का नियत किया जाना और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी पूर्व सेवा की गणना तथा धारणाधिकार/वर्गीकरण का अग्रनयन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

10 भर्ती नियमों का संशोधन—केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम उस विस्तार तक संशोधित किए गए समझे जाएंगे जो इन नियमों में उपबंधित है।

11 कतिपय मामलों में अधिशिष्ट कर्मचारी को प्रशिक्षण देना :

(1) यदि किसी प्रकोष्ठ के भारसाधक प्राधिकारी की राय है कि कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उपयोगिता पूर्वक पुनराभिनियोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कतिपय अतिरिक्त कौशल में प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाता है वह उसे किसी प्रशिक्षण के उपयुक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कर सकेगा।

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कर्मचारी अपने मूल संगठन के अधिशिष्ट कर्मचारी स्थापन पर बना रहेगा और उसे पहले के अनुसूच्य दर से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।

(3) प्रशिक्षण के दौरान अधिशिष्ट कर्मचारी प्रशिक्षण प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा जिसमें किसी आवासिक पाठ्यक्रम के मामले में उसका होस्टल में ठहरने के लिए भी शामिल है।

(4) किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के प्रशिक्षण पर रहते हुए भी, प्रकोष्ठ किसी उपयुक्त पद के लिए उसका नामांकन या उसकी अभ्यर्थिता प्रयोजित कर सकेगा और प्रस्ताव या नियुक्ति आदेश मिलने पर, प्रशिक्षण

के किसी प्रक्रम पर पड़ गड़न करने के लिए उसे अवसूक्त किया जा सकेगा।

(5) उसके लिए बिना उचित औचित्य के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से इंकार करने पर या उसे ग्रहण करने में विफल होने की दशा में, उसके अधिशिष्ट पद को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाई की जाएगी।

12 किसी भूतपूर्व अधिशिष्ट कर्मचारी का उसकी मूल सेवा, काडर या पदों के समूह में पुनराभिनियोजन के पश्चात् या लंबित रहते पुनः स्थानांतरण :

(1) नियम (4) के उपनियम (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, यदि समूह “ग” या समूह “घ” में किसी सेवा काडर या पदों के समूह में कोई नियमित और दीर्घकालिक रिक्ति उद्भूत होती है तो वह उक्त रिक्ति के होने की तारीख से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान वहां से अधिशिष्ट घोषित किए गए कर्मचारी या कर्मचारियों को पहले प्रस्तावित की जाएगी जो अन्यत्र पुनराभिनियोजित या पुनर्समायोजित किया जा चुका है/किए जा चुके हैं या जो पुनराभिनियोजित की प्रतीक्षा में है।

(2) यदि एक से अधिक ऐसे पुनराभिनियोजित कार्मिक (जिनमें वे भी जो पुनर्समायोजित हैं और वे भी जो संबंधित प्रकोष्ठ की पूंजी पर हैं पुनराभिनियोजित के लिए प्रतीक्षारत हैं, सम्मिलित हैं) उक्त रिक्ति में आमेहन के लिए विकल्प देते हैं तो प्रश्नाधीन सेवा, काडर या समूह में वह विकल्पी जो उनमें अधिशेष घोषित किया जाने से अन्यथा स्थिति में ज्येष्ठतम होता, उस पर नियुक्त किया जायगा।

(3) ऐसे पुनर्नियोजन पर नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता, सेवा, काडर या समूह में पुनः स्थापित की जाएगी जैसी कि उसके द्वारा उसके अधिशेष घोषित किए जाने से पूर्व उपभोगित थी।

(4) ऐसी दशा में पुनर्नियोजन स्थानांतरण यात्रा भत्ता और पद ग्रहण अवधि वेतन की ग्राह्यता के मामले में, स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण के रूप में माना जायगा।

[संख्या 1/14/89-सी एम-III]

ए. एम. तनेजा, निदेशक

परिशिष्ट

पुनर्समायोजन के लिए विकल्प का प्रारूप

[नियम 6 (2) देखिए]

मैं.....केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के निबन्धनों के अनुसार पुनर्समायोजन के लिए विकल्प देता हूं और इस प्रयोजन के लिए सुसंगत जानकारी नीचे देता हूं।

- नाम
(जैसा कि सेवा पुस्तिका में दिया हुआ है)।
- पिता का नाम
- जन्म की तारीख
- अधिवर्षिता की तारीख
- (क) वह कार्यालय जिसमें अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय नियोजित है।
(ख) अधिशिष्ट घोषित करते समय धारित पद
(ग) पद का वेतनमान
(घ) धारित पद का वर्गीकरण--समूह क/ख/ग/घ
(ङ) प्रास्थिति--स्थायी/स्थायीवत/अस्थायी/स्थानापन्न
(च) प्रवर्ग--अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/असुविधायक कार्मिक।
- बहु तारीख जिससे अधिशिष्ट घोषित किया गया है।

7. उस कार्यालय/पद की विशिष्टता जिसमें पुनराभिनियोजित किया गया है

- (क) कार्यालय का नाम और पता
(ख) कार्यालय में कार्यग्रहण की तारीख
(ग) वह पद जिस पर कार्यग्रहण किया गया
(घ) पद का वेतनमान

8. वर्तमान पता

स्थायी
कार्यालय का पता

9. पुनर्सेवा योजना चढ़ने के लिए कारणों से मुसंगत जानकारी

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) यदि निम्नतर वेतनमान वाले किसी वेतनमान में पुनराभिनियोजित का मामला है (स्वयं के अनुरोध पर से अभ्यथा) तो:—
पद से संलग्न वेतनमान

वह पद जिसे वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण कर रहा था।

वह पद जिसमें उसका पुनराभिनियोजन किया गया है।

1

2

(ख) यदि निम्नतर वर्गीकरण वाले पद में पुनराभिनियोजन का मामला है।

(i) मूल कार्यालय में धारित पद का नाम

(ii) क्या उसे समूह "क"/"ख"/"ग"/"घ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) उस पद का नाम और वर्गीकरण जिसमें उसका पुनराभिनियोजन किया गया है।

(iv) क्या कर्मिक और प्रशासनिक सुधार के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/15/84-के.से.-III तारीख 3-9-1984 के अधीन वर्गीकरण-प्रास्थिति के संरक्षण की सुविधा का उपभोग किया गया है, यदि नहीं तो उसके कारण बताएं।

(ग) यदि किसी ऐसे राज्य से भिन्न जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, राज्य में पुनराभिनियोजन के मामले में या किसी में नियोजन की व्यवस्था के लिए उपदर्शित किए जाने के मामले में जब वह पुनराभिनियोजन के लिए तैनात कर रहा हो। (केवल ऐसे समूह "घ"/समूह "ग" और ऐसे समूह "ख" के कर्मचारियों की दशा में जिनके वेतनमान का अधिकतम केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अनुसार 2900 रु. से अधिक नहीं है जिसके अन्तर्गत जहाँ अनुज्ञात हो वैयक्तिक वेतनमान भी है, को उपलब्ध है)।

(i) वह स्थान जिन पर अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान अवस्थित है.....

(ii) वह स्थान जिन पर वह पुनराभिनियोजन के समय तैनात किया गया और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान अवस्थित है.....

(iii) क्या संबंधित प्रकोष्ठ को किसी विशिष्ट राज्य में पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई अनुरोध किया गया था! यदि ऐसा है तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताएं जिसमें पुनराभिनियोजन के लिए अनुरोध किया गया था। इस संबंध में प्रकोष्ठ को किए गए निर्देश का ध्यान दें.....

(iv) (क) क्या पुनराभिनियोजन का पद कोई एकल पद है या किसी काडर सेवा का कोई भाग है.....

(ख) क्या पश्चात्तर्वर्ती मामले में काडर/सेवा में ऊपर (iii) या अनुकल्पन: (i) में (जो लागू हो) निर्दिष्ट राज्य में कोई ऐसा पद अवस्थित नहीं था जिसमें आवेदक को सामान्य अनुक्रम में अंतर्विभागीय रूप से स्थानांतरित किया जा सकता था.....

2. मैं यह समझता हूँ कि मेरी पूर्ण सेवा जिसके अन्तर्गत मेरे द्वारा धारित वर्तमान पद पर की गई सेवा भी है, उस पद पर जिसमें मैं पुनर्सेवायोजित किया जाता हूँ ज्येष्ठता के नियतन के मद्दे गणना नहीं ली जाएगी।

3. मैं यह भी समझता हूँ कि पुराने नियम के उद्दिष्ट (4) के खंड (ख) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में पुनर्सेवायोजन के लिए कार्यवाही बन्द हो जाएगी।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

विकल्पकर्ता का नाम-----

वर्तमान पदनाम-----

कार्यालय का पता-----

संख्या.....

तारीख.....

प्रणालि कलषा जाता है कि ऊपर वणित पदाधिकारी को इस संगठन में पुनराभिनियोजन पर कामिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय (अधिशिष्ट कर्मचारी) प्रकोष्ठ/रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के विशेष प्रकोष्ठ से अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन के लिए स्कीम के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था।

2. पदाधिकारी द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टताएं इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से सत्य पित कर ली गई हैं और ठीक पाई गई हैं।

3. ऊपर स्तंभ 9 (ग) के अर्थात् पुनर्समायोजन के मामले में:—

प्रस्तावित कर्मचारी का ऊपर उप स्तंभ (iii) में और अनुत्कल्पतः स्तंभ 9(ग) के उप स्तंभ (i) में उपदर्शित रीति से राज्य को अन्तर्विभागीय स्थानांतरण नहीं किया गया जा सकता है।

4. यह विकल्प इस विभाग/कार्यालय में तारीख.....माह.....वर्ष..... को प्राप्त हुआ था। पुनर्समायोजन के लिए उसकी पात्रता का केन्द्रीय मिबिल सेवा (अधिशिष्ट कर्मचारिवृद्ध पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के निबंधनों के अनुसार सत्यपन कर लिया है और तदनुसार पुनराभिनियोजन के लिए उक्त विकल्प अवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रोपित किया जाता है।

स्थान :

फोन सं. :

तार का पता :

(यदि कोई हो) :

हस्ताक्षर

कार्यालय अध्यक्ष

नाम और पदनाम

कार्यालय का पता

कार्यालय की मोहर

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1990

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Redeployment of Surplus Staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts (Group C) Rules, 1967, the Redeployment of Surplus Staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts (Group D) Rules, 1970, the Redeployment of Surplus Staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts (Group A and B) Rule, 1986, and the Redeployment of Surplus Staff in the Central Civil Services and Posts (Supplementary) Rules, 1989, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rule for regulating the redeployment and readjustment of surplus staff against vacancies in the Central Civil Services and Posts, namely :—

1. Short Title and Commencement : (1) These rules may be called the Central Civil Services (Redeployment of Surplus Staff) Rules, 1990 ;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Appendix' means Appendix to these rules ;

(b) 'Cell' means,

(i) in relation to the surplus staff belonging to Groups A, B and C, the Central

(Surplus Staff) Cell in the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, and—

(ii) in relation to Group D surplus staff, the Special Cell in the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour ;

(c) 'Commission' means the Union Public Service Commission ;

(d) "Controlling authority" means the authority competent under the rules regulating recruitment to a Central Civil Service or Post to take a decision for and initiate the process of filling of a vacancy in that service or post ;

(e) 'Readjustment' means the reappointment of an ex-surplus employee, though already deployed to another post, in accordance with these rules ;

(f) 'Redeployment' means the appointment of a surplus employee against a vacancy in a Central Civil Service or post in accordance with these rules ;

(g) 'Surplus staff' and 'surplus employee or employees' means the Central Civil Servants (other than those employed on ad-hoc, casual, work-charged or contract basis) who—

(a) are permanent or, if temporary, have rendered not less than five years' regular continuous service ; and

(b) have been rendered surplus alongwith their posts from the Ministries, Depart-

ments, Offices of the Government of India, as a result of—

- (1) administrative and financial reforms, including, inter-alia, restructuring of an organisation, zero base budgeting, transfer of an activity to a State Government, Public Sector Undertaking or other autonomous organisation, discontinuation of an on-going activity, and introduction of changes in technology; or
- (2) studies of work measurement undertaken by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance or any other body set up by the Central Government or the Ministry/Department concerned; or
- (3) abolition or winding up either in whole or in part of an organisation of the Central Government;

(h) 'Rolls' mean the list of surplus staff currently under redeployment or readjustment through the Cell.

3. Reporting of Vacancies to the Cells :

(1) Vacancies in the Central Civil Services and Posts in Groups 'A' and 'B'

- (i) The controlling authority in respect of a Group 'A' or Group 'B' Service or post in which any vacancy is to be filled up by direct recruitment through the Commission (otherwise than on the basis of a competitive examination) shall, while sending requisition for the purpose to the Commission, also simultaneously send a copy thereof to the Cell.
- (ii) The Commission shall not entertain a requisition placed for the purpose unless it indicates that a copy thereof has simultaneously been sent to the Cell and shall take action for recruitment to the posts notified to the Commission in the usual manner only if—
 - (a) no recommendation is received by it from the Cell within a period of 15 days from the date of receipt of the requisition in its office sponsoring the surplus employee or employees for appointment against such vacancy or vacancies, or
 - (b) the candidate(s) recommended for consideration by the Cell is (are) not found suitable by the Commission for appointment to the post(s) in question.
- (iii) Where a post is to be filled up by transfer in consultation with the Commission, the controlling authority in respect of the post shall first intimate the vacancy to the Cell, who, if it has a surplus employee in its rolls who is prima-facie suitable for appointment thereto, shall sponsor him to the Commission. Under intimation to the controlling authority concerned, for

considered for absorption against the post in question. Such a post will be circulated only if (a) the Cell communicates the non-availability of a suitable surplus employee from its rolls to sponsor for absorption in it, or (b) the Commission holds the surplus employee sponsored by the Cell to be unsuitable for appointment to the post.

(iv) All vacancies in Central Civil Services and posts in Groups 'A' and 'B', which are to be filled by direct recruitment or by transfer but otherwise than through the Commission, shall first be reported to the Cell and shall be filled from amongst the surplus staff, unless the controlling authority of the service or post in question has ascertained from the Cell that they have no suitable persons from amongst the surplus staff available with them for being nominated against the particular post.

(v) The provisions contained in sub-rule (1) shall not apply to the posts and services under the administrative control of—

- (a) the Departments of (i) Atomic Energy, (ii) Space, (iii) Electronics, (iv) Indian Audit and Accounts, (v) Railways (excluding the posts located in the Headquarters Offices of the Railway Board);
- (b) the Ministry of Defence (lower field formations other than the Defence Research and Development Organisation);
- (c) the various security and para-military organisations under the Ministries of Home Affairs and Defence, and Cabinet Secretariat;

Provided that this shall not debar the controlling authority of such services or posts to request the Cell to sponsor suitable surplus employees, and to appoint them.

(2) Vacancies in the Central Civil Services and Posts in Groups 'C' and 'D'—

- (i) All vacancies in the Central Civil Services and Posts in Groups 'C' and 'D', except those covered by clause (iii) of this sub-rule and clause (a) of sub-rule (4), shall be filled from amongst the surplus staff sponsored by the concerned Cell.
- (ii) The Government departments or offices may fill vacancies in accordance with the normal procedure only after ascertaining from the concerned Cell that they have no suitable persons from amongst the surplus staff available with them for the particular post.
- (iii) The vacancies of the following categories need not be reported to the Cell concerned :
 - (a) those to be filled by transfer on deputation;
 - (b) those to be filled on ad-hoc or short term basis, appointments to which have no

prospects of being continued indefinitely and being finally regularized :

- (c) those to be filled by promotion, where eligible candidate, having prescribed qualifications for promotion are available in the feeder cadre(s) :
- (d) those located in the Ministries or Departments, referred to in sub-clauses (a) and (b) of clause (v) of sub-rule (1) ;
- (e) those located in the organisations referred to in sub-clause (c) of clause (v) of sub-rule (1) which are to be filled otherwise than through open recruitment ;
- (f) those in posts on the personal staff of a high dignitary, appointment to which is to be made at the discretion of such dignitary ;
- (g) those to be filled by appointment on compassionate grounds of the dependent(s) of deceased Government Servants.
- (h) those in the Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers Service, and the Central Secretariat Clerical Service;
- (i) those being utilised for making appointments under sub-rule (6) of rule 4 and rule 12.

(3) Withdrawal of vacancies

No vacancy which has been reported to the Cell and against which a surplus employee has been either nominated by the Cell or, in the case of a vacancy reported under clause (i) or (iii) of sub-rule (1) above, recommended by the Commission, shall be withdrawn :

Provided that where the withdrawal of such a vacancy is considered necessary, request for it shall be made by, or with the express approval of, the Secretary of the administrative Ministry, giving reasons for the same.

Provided further that in the case of any doubt or controversy regarding the need or propriety of withdrawing the vacancy, the administrative Ministry or Department shall abide by the decision of the Department of Personnel and Training.

(4) Selective reporting of vacancies to the Cells :

Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3) the concerned Cell may issue instructions that, —

- (a) the Ministries and Departments need not report vacancies in certain posts, grades, services or regions, as may be specified, to the Cell either for any specific period or till further instructions to the contrary are issued, and
- (b) vacancies existing in particular posts, grades, services or regions at any point of time should be reported to it, and should not be filled up through any other modes including those prescribed in the Recruitment Rules, except after obtaining a specific clearance from the Cell aforesaid.

4. Redeployment of Surplus Staff

(1) Against vacancies in Groups 'A' and 'T' Services or posts

- (i) The surplus employees recommended by the Cell will be entitled to first priority for appointment to the vacancies in Group 'A' and 'B' Services or posts filled by direct recruitment including those filled through the Commission (otherwise than on the basis of a competitive examination held by the Commission), or by transfer :

Provided that they are found suitable by the Commission or other prescribed authority and no suitable disabled defence services personnel are available with them for appointment to such vacancies.

- (ii) The Cell shall recommend to the Commission the name of a surplus employee who, for the time being, is borne on its rolls, for being considered for appointment to a specific post, wherein the vacancy has been notified to the Commission and to the Cell, and for appointment to which the surplus employee concerned appears to the Cell to be prima facie suitable, having regard to the scale of pay attached to the post and the one held by him, his qualifications and the relevance of his previous experience.

- (iii) The Cell may recommend more than one surplus employee on its rolls for being considered for appointment to a post for which each of them seems to it to be prima-facie suitable for appointment.

- (iv) The Commission may consider any surplus employee whose bio-data has been referred to it by the Cell, for appointment to a post, even if he has not been specifically recommended by the Cell for that post; provided (a) the post in question carries the same scale of pay or has the same maximum of the pay scale as the one held by him, (b) the surplus employee is found suitable for appointment to such post in preference to the other posts for which his candidature may have been sponsored by the Cell, and (c) he does not suffer from any of the disabilities mentioned in clause (v) of this sub-rule.

- (v) The Cell shall not recommend the name of a surplus employee to the Commission, —

- (a) if on being sponsored by the Cell he has already been recommended by the Commission for appointment to a post in a Central Government Department carrying a pay-scale not lower than his existing pay scale;
- (b) if he has joined another post in the meantime, whether on redeployment through the Cell, or otherwise, or has asked for reversion to another continuing post on which he holds a lien;

- (c) if he is due for superannuation within six months from the date of his transfer to the rolls of the Cell;
 - (d) if his services are terminated or he is to be retired (including premature or voluntary retirement on the basis of a notice given by the surplus employee) or discharged from service or otherwise ceases to be on the rolls of the Cell on any date before the expiry of six months from the date of his transfer to the rolls of the Cell; (e) for absorption in a post which lies outside the parameters of placement laid down in rule 5.
 - (vi) The Commission may, in its discretion, consult the confidential reports written earlier on a surplus employee or, if necessary, call him for interview to determine his suitability for appointment to a post but shall not subject him to a written test for this purpose.
 - (vii) The Commission may, in its discretion, relax the educational qualifications, experience etc., prescribed for recruitment to a service or post, in respect of any member of the surplus staff sponsored by the Cell for appointment to such service or post, if the surplus candidate is otherwise considered by them to be suitable for appointment to the service or post in question.
 - (viii) The Commission shall, as far as possible, finalise and communicate to the Cell its assessment of suitability or otherwise of a surplus employee recommended by the Cell for a post within one month from the date of receipt of such recommendation in its office.
- (2) Against vacancies in Groups 'C' and 'D' Services or posts
- (i) The surplus staff nominated by the Cell shall enjoy first priority for appointment against a vacancy, after the disabled defence services personnel.
 - (ii) The surplus staff sponsored by the concerned Cell for redeployment against vacancies in Group 'C' or Group 'D' Central Civil Services and posts, as the case may be, shall not be subject to any tests or interviews for the purpose of appointment, unless otherwise decided by, or in consultation with, the Cell concerned.
 - (iii) The surplus staff shall not be ineligible for appointment in the recipient organisation on the ground that they do not possess the minimum educational qualifications prescribed for the posts to which they are redeployed by the Cell except in cases where certain minimum technical qualifications are prescribed for a particular post :

as unsuitable for appointment to a post, merely on grounds of not possessing the educational or technical qualifications prescribed for appointment thereto, if he has satisfactorily completed probation therein, or if he was not required to be placed on probation, his performance therein during the preceding period of not less than two years has been reported to be satisfactory.

- (iv) If the Cell in the Department of Personnel and Training, on review of the vacancies reported to it, comes to the conclusion that it may not be possible for it to arrange a suitable placement in a Group 'C' post, it may, as far as possible with prior intimation to the Cell in the Directorate General, Employment & Training, nominate a Group 'C' surplus employee for appointment to a vacancy in a Group 'D' Service or post, and in that case, these rules shall apply to such nomination, as are applicable to the nomination of a Group 'D' surplus employee made by the Cell in the said Directorate General :

Provided that where nominations are made by the Department of Personnel & Training as well as by the Directorate General, Employment and Training for the same vacancy, the recipient organisation shall act upon the nomination received by it first and shall inform the other organisation to divert its nomination elsewhere.

(3) Redeployment of surplus officiating employees :

- (a) An employee, who is officiating in a post declared surplus, shall be eligible for redeployment to a post as per clause (i) of sub-rule (1) of rule 5, provided that, —
 - (i) he was appointed to such post through the regular process of promotion or transfer and there was, in the ordinary course, no prospect of his reversion from it within a period of six months from the date from which he is declared surplus;
 - (ii) he does not, suo motu, opt for being reverted to a post on which he holds a lien; and
 - (iii) he is not due for superannuation, and has not asked for being allowed to retire under the rules applicable to him from a date within the aforesaid period of six months.
- (b) A surplus officiating employee shall revert to the post on which he holds a lien, whether administrative or substantive (unless such post has already been abolished or declared surplus), at the expiry of a period of six months from the date from which he was declared surplus, if no placement in an appropriate post can be arranged for him within such period, or he refuses to accept the placement arranged for him, or fails to join such placement within the joining time allowed by the authority under whom such placement is located.

Provided that where a surplus employee is already holding an equivalent post with substantially identical duties on a regular basis, he will not be treated

- (c) The provisions of clauses (a) and (b) above shall not be applicable to the case of an employee who has satisfactorily completed his probation in the post held by him or was, under any general or special orders of the competent authority, exempt from being placed on probation on such officiating appointment.

(4) Determination of suitability of surplus employees for appointment to posts other than those filled through the Commission :

The following authorities shall have the power to determine the suitability of surplus staff for appointment to the posts, filled otherwise than through the Commission, as shown below, where necessary by relaxation of the qualifications, experience, etc., prescribed under the relevant recruitment rules :

- (a) The Department of Personnel and Training in respect of employees nominated against,—
- (i) vacancies in Groups 'A' and 'B' Services and posts reported under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 3, and
 - (ii) vacancies in Group 'C' Services and posts except those located in the Ministries, Departments etc. mentioned in clause (v) of sub-rule (1) of rule 3, and
 - (iii) vacancies in Group 'D' Services and posts utilized under clause (iv) of sub-rule (2) of this rule for redeployment of Group 'C' surplus staff.
- (b) The Ministry or the Department concerned in respect of employees nominated against vacancies in the Ministries, Departments, etc., mentioned in clause (v) of sub-rule (1) of rule 3.
- (c) The Directorate General, Employment & Training, Ministry of Labour in respect of Group 'D' employees nominated against Group 'D' Services and posts, other than those referred to in clause (iv) of sub-rule (2) above.

(5) Appointment of surplus employees recommended by the Commission or Cell :

- (i) The administrative Ministry or Department shall, on receipt of the recommendation made by the Commission or nomination made by the Cell, for appointment of a surplus employee to a post or service for which a requisition had earlier been placed upon the Commission or the Cell, as the case may be, take immediate action to issue the orders of appointment of the surplus employee concerned under advice to the Cell and, where relevant, the Commission.
- (ii) The appointing authority of the recipient " " make an offer of appointment forthwith on the terms and conditions regulating redeployment of surplus

staff and shall not impose any contrary conditions of its own, except where required under a law, without prior consultation with the Cell.

- (iii) The recipient organisation shall accept a surplus employee, who in the absence of a response or reaction from it within one month is relieved by the parent organisation on the directions issued by the Cell concerned.

(6) Absorption of surplus staff within the Ministry or Department :

Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3), (4) and (5), and subject to the provisions of rule 12, the Ministry or Head of Department may, under intimation to the concerned Cell, adjust an employee declared surplus by it against a vacancy (if any available at the time he is declared surplus or before he is redeployed through the Cell) in any post located in any office under its control and carrying equivalent pay scale for appointment to which he is considered by the appointing authority to be suitable.

(7) Conclusion of action for redeployment of a surplus employee.

The action for redeployment of a surplus employee shall be deemed to have been concluded on the date on which,—

- (a) he is relieved to join another post, in the same or another Department or organisation, whether arranged through the Cell or otherwise; or
- (b) his request for termination of services or resignation or voluntary or premature retirement is accepted.

5. Determination of Placement : (1) (i) As far as possible, a surplus employee shall, subject to his suitability, be redeployed in a post carrying a pay-scale matching his current pay scale.

(ii) For the purpose of clause (i), a matching pay-scale shall mean a pay-scale the maximum of which is equal to that of the pay-scale of the surplus employee, and the minimum of which is not higher than the basic pay (including the stagnation pay) which the surplus employee is in receipt of at the time of making his nomination.

(2) Where a suitable vacancy in a post carrying matching scale of pay is not available, the surplus employee may be redeployed in a post carrying a non-matching pay scale :

Provided that, —

- (i) the maximum of the pay scale of such post does not exceed the maximum of the pay-scale of the surplus employee by more than 10 percent; and

- (ii) such post is not lower than the post which forms, or would ordinarily form, the next lower rung in the promotional ladder for the incumbents of the post of the level currently held by the surplus employee :

Provided, further, that, —

- (i) a surplus employee who is sponsored or nominated against a post carrying a pay scale with a higher maximum, in terms of clause (i) of the first proviso above should either have the qualifications, as prescribed for appointment to the post by direct recruitment or by transfer, or should have been successfully performing in his parent department the duties attached to such post; and

- (ii) when redeployed in a post carrying a lower scale of pay, the surplus employee shall be permitted to carry his current pay-scale alongwith him to the next post but this benefit shall not be extended where, despite availability of a post in a matching or a higher pay-scale, a person is redeployed in a post carrying a lower pay-scale at his own request.

(3) Where a surplus employee is drawing pay in a pay-scale different from those prescribed under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986, the administrative Ministry shall while reporting the particulars of such employee to the concerned Cell for arranging his redeployment, or as soon as may be thereafter, also communicate to the Cell, the pay-scale under the aforesaid rules, corresponding to his pay-scale, as may be determined in consultation with the Ministry of Finance having regard to the duties and responsibilities attached, and qualifications prescribed for appointment to the post held by him. For the purpose of his placement under this rule and under rule 6, the employee will be deemed as borne on such corresponding pay-scale of the said Revised Pay Rules, as determined under this rule.

6. Readjustment of Redeployed Surplus Staff :

(1) A surplus employee who has already been redeployed shall not be eligible to seek readjustment, except in the following cases :

- (a) when redeployed, otherwise than at his own request, —
- (i) in a post carrying a pay-scale lower than the pay-scale on which he was borne at the time of being declared surplus; or
 - (ii) in a post carrying a lower classification than that of the post held by him at the time of being declared surplus; or
 - (iii) in the case of an employee whose maximum of pay-scale, as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 did not exceed Rs. 2900/-, in a State other than the State(s) in which

he had requested for his placement to be arranged while awaiting redeployment and, in the absence of such request, the State in which he was posted at the time of being declared surplus :

Provided that he is not, in the ordinary course, eligible to seek intra-departmental transfer to such State(s) of choice or posting, as the case may be :

Provided, further, that he does not fall under the category which have All India Transfer Liability”.

(b) if his case falls into any other class of cases, as may be specified by the Central Government by an order as being eligible for seeking readjustment under these rules.

(2) A redeployed employee, who in terms of sub-rule (1) is eligible to seek readjustment, shall exercise an option in favour of such readjustment in the form given in the Appendix and shall transmit the same to the Department of Personnel and Training (Surplus Cell) or—in the case of Group ‘D’ employees—to the Directorate General of Employment and Training, New Delhi, through his head of office within two months from the date of joining the post in which he has, for the time being, been redeployed.

(3) In the event of the option being found acceptable, the existing redeployment of the employee shall be treated as provisional and the employee concerned shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the definition of the term ‘Surplus Staff’, be treated notionally to be a surplus employee awaiting final redeployment.

(4) The readjustment shall be subject to the following further conditions :—

(a) The surplus employee shall have no claim to count his past service, including that rendered in the post of his provisional redeployment, towards fixation of seniority in the post in which he is readjusted.

(b) The action for readjustment shall be treated as concluded :—

(i) on the expiry of six months (excluding the period of suspension/disciplinary proceedings, if any) from the date on which the option for readjustment is exercised; or

(ii) on such earlier date on which an order of appointment to a post carrying a matching scale of pay and/or equivalent classification in respect of those covered by sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) sub-rule (1) above, and in the appropriate State, in respect of those covered by sub-clause (iii) thereof, is made to the employee; or

(iii) if the employee withdraws option for readjustment or tenders resignation or

gives notice for voluntary retirement or retires or otherwise ceases to be in service; and, —

- (iv) in the case of an employee who is placed under suspension or becomes the subject of disciplinary proceedings against him, during the period of such suspension or currency of disciplinary proceedings, as the case may be.
- (c) Readjustment shall be only against a vacancy available in a Central Ministry, Department or subordinate office and reported to the concerned Cell.
- (d) A surplus employee already redeployed in a post carrying a higher pay scale may be readjusted in a post carrying a pay-scale matching his original pay-scale and shall have no claim for being readjusted in a post carrying such higher pay-scale nor shall he be entitled to protection of such higher pay-scale in the new post.
- (e) A surplus employee redeployed in a post carrying a lower pay-scale who seeks readjustment under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (a) of sub-rule (1) above shall be eligible for protection of status in terms of Department of Personnel and AR's O.M. No. 1/15/84-CS.III dated 3-9-1984, if finally also he is readjusted in a post carrying a lower classification but shall not be eligible to seek further readjustment on that account.
- (f) The surplus employees awaiting initial redeployment shall have prior claim to adjustment against the vacancies reported by the Ministries/Departments/Offices to the Department of Personnel & Training or the Directorate General of Employment and Training, as the case may be, and the possibilities of adjustment of the provisionally redeployed employees shall be explored against the remaining reported vacancies which have not already been permitted to be filled through the normal channels of recruitment.
- (g) No request for adjustment in a particular district or town or department or post shall be entertained.

(5) The appointment of an employee by way of readjustment in terms of these rules shall be treated as appointment by transfer in public interest for the purposes of grant of transfer Travelling Allowance, joining time and joining time pay.

(6) The benefits of protection of permanent status and of past service shall be admissible to an employee on readjustment under these rules, on the same terms, as to a surplus employee on his redeployment.

(7) The vacancies reported to the Cell in question under rule 3 may be utilized by the appropriate Cell for readjustment of redeployed staff in terms of these rules, if there is no suitable surplus

employee for being nominated or sponsored there-against at the relevant time.

(8) The provisions contained in rules 4 (except sub-clauses (a) and (b) of clause (v) of sub-rule (1) and sub-rule (7) thereof); 5,7,8,9 and 10 of these rules shall also apply in respect of readjustment of redeployed surplus employees.

(9) The acceptance of the option of an employee for readjustment shall not per se confer any immunity upon him from undergoing any training, passing any departmental test or performing any duties as may be required of him by the rules applicable to the post held by him, or under the order of the competent authority, in the office of provisional redeployment.

7. Age Limit : The upper age limit shall not apply in the case of a surplus employee appointed under these rules.

8. Medical Examination.—The surplus staff redeployed by the Cell shall not be required to undergo fresh medical examination unless different medical standards have been prescribed for the post in the recipient organisation or unless the person concerned had not been medically examined in respect of his previous post or, if examined, had been declared medically unfit.

9. Fixation of Pay and Seniority, Counting of Previous Service for Various Other Purposes and Carrying Over of Lien/Classification : The fixation of seniority and pay of the surplus employee and counting of his previous service for various other purposes and carrying over of lien/classification in the new post to which he is appointed on redeployment under these rules shall be regulated in accordance with the instructions issued from time to time by the Government of India in this behalf.

10. Amendment of Recruitment Rules : All rules regulating the recruitment of person to the Central Civil Services and posts shall be deemed to have been amended to the extent as provided for in these rules.

11. Imparting of Training to Surplus Staff in Certain Cases : (1) If the authority in charge of a Cell is of the opinion that a surplus employee cannot be usefully redeployed unless he is given training in certain additional skills, it may nominate him to a suitable course of training.

(2) During the period of training the employee shall continue to be borne on the Surplus Staff Establishment of his parent organisation and shall be paid pay and allowances at the rates already admissible to him.

(3) During training the surplus employee shall abide by the directions of the training authority, including those for his staying in hostel in the case of a residential course.

(4) Notwithstanding that a surplus employee is on training, the Cell may nominate him or sponsor his candidature for any suitable post, and on receipt of offer or orders of appointment, he may, at any,

stage during the course, be relieved to join the post.

(5) In the event of refusal to join the training course or failure to join the same, without providing proper justification therefor, action shall be taken to abolish his surplus post forthwith.

12. Retransfer of a Former Surplus Employee to his Original Service, Cadre or Group of Posts After or Pending Redeployment.

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 4, if a regular and long-term vacancy arises in a service, cadre or group of posts, in Group 'C' or 'D', it shall first be offered to the employee or employees declared surplus therefrom during a period of one year preceding the date of occurrence of the vacancy, who has/have been redeployed or readjusted elsewhere or is/are awaiting redeployment.

(2) If more than one such redeployed personnel (including those readjusted and those awaiting redeployment on the rolls of the concerned Cell) opt for being absorbed against such vacancy, the optant who would have been the seniormost amongst them in the service, cadre or group in question, but for having been declared surplus, shall be appointed thereto.

(3) On such re-appointment, the appointee shall be restored his seniority in the service, cadre or group, as was enjoyed by him therein prior to his being declared surplus.

(4) The re-appointment in such cases shall be treated as transfer at own request in the matter of admissibility of transfer Travelling Allowance and joining time pay.

[No. 1/14/89-CS.III]

A. S. TANEJA, Director.

APPENDIX

FORM OF OPTION FOR READJUSTMENT

[See Rule 6(2)]

I, hereby exercise option for readjustment in terms of rule 6 of 'The Central Civil Services (Redeployment of Surplus Staff) Rules, 1990 and furnish below the relevant information by the purpose :

1. Name

(as given in the Service Book)

2. Father's name

3. Date of birth

4. Date of superannuation : HHH HHHH HHHH

5. (a) Office in which employed at the time of being declared surplus

(b) Post held when declared surplus

(c) Pay scale of the post.

(d) Classification of the post held

(e) Status

(f) Category

*Group A/B/CD

*Permanent/Quasi-Permanent/Temporary/Officiating

*Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Ex-Service-man/Handicapped Personnel.

6. Date from which declared surplus

7. Particulars of Office/post in which redeployed

(a) Name and address of office

(b) Date of joining the office

(c) Post joined

(d) Pay scale of the post

Present Address

Permanent

Office Address

9. Information relevant to the reasons for seeking readjustment :

(A) In a case of redeployment in a post carrying a lower pay scale (otherwise than on own request)—

Pay scale attached to the post

1

2

held at the time of being
declared surplus

in which redeployed

*Strike whichever is inapplicable.

(B) If a case of redeployment in a post carrying lower classification—

- (i) Nomenclature of the post held in parent office
- (ii) Whether it was classified as Group 'A'/'B'/'C'/'D'
- (iii) Nomenclature and classification of the post in which redeployed
- (iv) Whether facility of protection of classification-status availed of under DP&AR O.M. No. 1/15 84-CS-III dated 3-9-1984, if not, reasons therefor:

(C) If a case of redeployment in a State other than the one in which posted at the time of being declared surplus, or the one indicated for arranging placement in, when awaiting redeployment (available only in the case of Group 'D'/Group 'C' and such Group 'B' employees whose maximum of pay scale (including personal pay scale where allowed) as per CCS (Revised Pay) Rules, 1986 does not exceed Rs. 2900/-)

- (i) Station at which posted at the time of being declared surplus and the State/U.T. in which it is located
- (ii) Station at which posted on redeployment and the State/U.T. in which it is located
- (iii) Whether any request was made to the concerned Cell for arranging redeployment in any particular States; if so, name the State/U.T. in which redeployment was requested. Furnish details of reference made to the Cell in this regard.
- (iv) (a) Whether the post of redeployment is an isolated post or forms part of a cadre/service
- (b) In the latter case, whether the cadre/service has no post located in the State referred to in (iii) or alternatively (i) above (as applicable) to which the applicant can be transferred intra-departmentally in the normal course

2. I understand that my past service including that rendered in the post at present held by me, shall not count towards fixation of seniority in the post in which I am readjusted.

3. I also understand that the action for readjustment shall stand closed in any of the circumstances mentioned in clause (b) of sub-rule (4) of rule 6 ibid

Date:

Signature

Station:

Name of the Optant

Present designation

Office address

No. Date

Certified that the above-mentioned official was appointed to this organisation on redeployment from the Central (Surplus Staff) Cell of the Department of Personnel and Training/Special Cell of the Directorate Genral of Employment and Training in terms of the Scheme for Redeployment of Surplus Staff.

2 The particulars furnished by the official, as above, have been verified with reference to the records available in this office and have been found to be correct.

3 In case of readjustment under column 9(C) above:

The employee in question cannot be transferred intra-departmentally to the State indicated in sub-col. (iii) and alternatively in sub-column (i) of column 9(C) in the proforma above.

4 The option was received in this Department/Office on (Date)—(Month) —(Year) —His eligibility for readjustment in terms of rule 6 of the Central Civil Services (Redeployment of Surplus Staff) Rules, 1990, has been verified and accordingly his option for readjustment is forwarded for necessary action.

Station :

(Signature of Head of Office)

Phone No.

Name & designation

Telegraphic address (if any)

Office Address

Office stamp

